



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2972]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2019/भाद्र 20, 1941

No. 2972]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2019/BHADRA 20, 1941

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2019

का.आ. 3248(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	सदस्य	प्रास्थिति
1.	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार।	अध्यक्ष पदेन
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), आरण्य भवन, सेक्टर-10ए, गांधीनगर।	सदस्य पदेन
3.	उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गुजरात समुद्रीय बोर्ड, गांधीनगर।	सदस्य पदेन
4.	सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधीनगर।	सदस्य पदेन
5.	उद्योग आयुक्त, उद्योग भवन, गांधीनगर।	सदस्य पदेन
6.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गुजरात राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गांधीनगर।	सदस्य पदेन
7.	मुख्य नगर योजनाकार, गुजरात राज्य, गांधीनगर।	सदस्य पदेन

8.	सदस्य सचिव, गुजरात पारिस्थितिकी आयोग, गांधीनगर ।	सदस्य पदेन
9.	मछली उद्योग आयुक्त, गुजरात राज्य, गांधीनगर ।	सदस्य पदेन
10.	श्री टी.पी.सिंह, निदेशक, भास्कराचार्य, अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान, गांधीनगर ।	सदस्य (विशेषज्ञ)
11.	श्री राजेश प्रवीण चंद्र डोशी, नौ इंजीनियर, वडोदरा ।	सदस्य (विशेषज्ञ)
12.	श्री एच.बी.चौहान, सेवानिवृत्त ज्येष्ठ वैज्ञानिक, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद ।	सदस्य (विशेषज्ञ)
13.	डा.सी.एन.पांडे, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्लॉट नं.726/बी, सेक्टर-8-सी, गांधीनगर ।	सदस्य (विशेषज्ञ)
14.	श्री राजेश आई. शाह, प्रबंध न्यासी, विकास, ईशावास्यम विकास केन्द्र, लाजपतनगर के सामने, ईशिता टावर रोड, नवरंगपुरा, नवजीवन, अहमदाबाद-380014 ।	सदस्य, गैर शासकीय संगठन ;
15.	निदेशक (पर्यावरण) और अपर सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, गांधीनगर ।	सदस्य सचिव, पदेन ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात स्थित गांधीनगर में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण, गुजरात राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनियम जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा ; और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जैसा अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।

7. प्राधिकरण, छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

[फा. सं. जे-17011/30/99-आईए.-III(भाग)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### ORDER

New Delhi, the 9th September, 2019

**S.O. 3248(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Gujarat Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

S.N.	Members	Status
1.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Forest and Environment, Department, Government of Gujarat.	Chairman, <i>ex-officio</i> ;
2.	Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), Aranya Bhavan, Sector-10 A, Gandhinagar.	Member, <i>ex-officio</i> ;
3.	Vice Chairman and Chief Executive Officer, Gujarat Maritime Board, Gandhinagar.	Member, <i>ex-officio</i> ;
4.	The Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board, Gandhinagar.	Member, <i>ex-officio</i> ;
5.	The Industries Commissioner, Udhog Bhavan, Gandhinagar	Member, <i>ex-officio</i> ;
6.	Chief Executive Officer, Gujarat State Disaster Management Authority, Gandhinagar.	Member, <i>ex-officio</i> ;
7.	Chief Town Planner Gujarat State, Gandhinagar.	Member, <i>ex-officio</i> ;
8.	Member Secretary, Gujarat Ecology Commission, Gandhinagar.	Member, <i>ex-officio</i> ;
9.	The Commissioner of Fisheries, Gujarat State, Gandhinagar.	Member, <i>ex-officio</i> ;
10.	Shri T. P. Singh, Director, Bhaskaracharya Institute of Space Application and Geo-informatics, Gandhinagar.	Member, ( <i>Expert</i> );
11.	Shri Rajesh Pravin Chandra Doshi, Marine Engineer, Vadadara.	Member, ( <i>Expert</i> );
12.	Shri H. B. Chauhan, Retired Senior Scientist, Space Application Centre, Ahmedabad.	Member, ( <i>Expert</i> );
13.	Dr. C. N. Pandey, Retired Principal Chief Conservator Forest, Plot No. 726/B, Sector -8-C, Gandhinagar.	Member, ( <i>Expert</i> );
14.	Shri Rajesh I. Shah, Managing Trustee, VIKAS, Centre for Development Ishavasyam, Opposite Lajpatnagar, Eeshita Tower Road, Navarangpura, Navjeevan, Ahmedabad-380014.	Member, Non-Governmental Organization;
15.	Director (Environment) and Additional Secretary, Forests and Environment Department, Gandhinagar.	Member Secretary, <i>ex-officio</i> .

2. The Authority shall have its headquarters at Gandhinagar, Gujarat.
3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.
4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.
5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Gujarat, take the following measures, namely:—
  - (i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;
  - (ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;
  - (iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;
  - (iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;
  - (v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;
  - (vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;
  - (vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;
  - (viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.
6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meetings, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the Courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.
7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/30/99-IA.-III(Pt.)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.